Subsidy on Foodgrains

1575. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the estimated quantum of subsidy given on foodgrains of mass consumption distributed through the PDS during 1992-93, 1993-94 and so far in 1994-95;

(b) the break-up of the subsidy between the producer and the consumer; and

(c) the quantum of subsidy for channelisation the Food Corporation of India in its role as the producer from the grower, stockist and distributor to the PDS outlets?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a), (b) and (c) Food subsidy is paid to the Food Corporation of India for reimbursement of (i) difference between economic cost of foodgrains and their issue prices viz. consumer subsidy and (ii) carrying cost of buffer stocks. During that years 1992-93 and 1993-94 a sum of Rs. 2,785 crores and Rs. 5,537 crores respectively was paid to the Food Corporation of India towards food subsidy.

During the current financial year 1994-95, a sum of Rs. 1,491 crores has been released so far on this account. The food subsidy provided by the Ministry has no subsidy component for producers.

मध्य प्रदेश में बेस डिपुओं का खोला जाना

1576. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के 55 बेस डिपो मध्य प्रदेश के केवल 35 जिलों में स्थित हैं और शेष जिलों में ऐसे कोई डिपो नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास शेष 10 जिलों में भी ऐसे बेस डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश के दस राजस्व जिलों में अपने कोई डिपो नहीं हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम केवल ऐसे नोडल केन्द्रों पर अपने आधार डिपुओं का निर्माण करता है, जो अन्य राज्यों से खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिये रेल द्वारा अच्छी तरह जुड़े होते हैं और वहीं से ही इन डिपुओं को परिचालित करता है । आधार डिपो वसूली क्षेत्रों और प्रमुख खपत/बफर केन्द्रों में स्थापित किये जाते हैं ।तथापि, ऊपर उल्लिखित दस राजस्व जिलों में भारतीय खाद्य निगम निकटवर्ती जिलों में अपने डिपुओं से स्टाक सप्लाई करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अबाध आपूर्ति बनाये रखता है ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम का इन दस राजस्व जिलों में आधार डिपुओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ये जिले न तो प्रमुख वसूली वाले क्षेत्र हैं और न ही प्रमुख खपत वाले केन्द्र हैं । राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता का नामित डिपुओं से उठान करती है और यह प्रबंध सतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । इन जिलों में छोटे-छोटे वितरण डिपो हैं जिनका रख-रखाव राज्य सरकार और नागरिक आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता हैं ।